E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव

डॉ. सीताराम सिंह तोमर

प्राचार्य, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14467703

भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। आजादी मिलने के बाद 1951 से आयोजन के सहारे यह विकास कार्य में संलग्न है। अतीत की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था इस दौरान विकास की दिशा में निःसंदेह आगे बढ़ी है लेकिन इस विकास के बावजूद जनसाधारण की गरीबी और बेरोजगारी पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया है। उनका जीवन स्तर अभी भी बहुत नीचा और असंतोषजनक है। अतः विकास कार्य का संचालन इस ढंग से किया जाना चाहिए, जहाँ एक ओर विकास की गति तेज हो सके, वहीं दूसरी ओर देश के जनसाधारण को सामाजिक न्याय उपलब्ध हो और उनका जीवन स्तर सही अर्थ में ऊपर उठ सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं– (1) प्रतिव्यक्ति नीची आय (2) प्राकृतिक संसाधनों का अल्प प्रयोग (3) कृषि की प्रधानता (4) कमजोर औद्योगिक ढाँचा (5) सेवा क्षेत्र का पिछड़ापन (6) उपभोग वस्तुओं के आयात की प्रधानता (7) पूँजी की कमी और तकनीक का निम्न स्तर (8) जनसंख्या की अधिकता (9) पिछड़ा आर्थिक और सामाजिक ढाँचा (10) दोषपूर्ण बाजार व्यवस्था।

उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है लेकिन जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को विगत कुछ वर्षों के संदर्भ में देखते हैं तब इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनके आधार पर इसे विकासशील कहा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को स्पष्ट करने वाले तत्त्वों को निम्न प्रकार उल्लेख किया जा सकता है –

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

1. प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि।
2. बचत और विनियोग का ऊपर उठना।
3. उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
4. आर्थिक और सामाजिक पूँजी में उन्नति।
5. संस्थागत ढाँचे में सुधार इत्यादि।

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में विकासोन्मुख तो है, लेकन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों एवं अपनी आशाओं की दृष्टि से विकास की गति धीमी है और अनियमित भी। गरीबी और बेकारी पर अभी विशेष प्रभाव नहीं पड़ सका है। साथ ही विकास का लाभ मुख्यतः बड़े–बड़े उद्योगपति, व्यापारी, ठेकेदार, अफसर आदि जैसे इने–गिने लोग ही हड़प लेते हैं। लाभ का बहुत छोटा भाग जनसाधारण को मिल पाता है। फलस्वरूप आम लोगों के जीवन स्तर में कोई खास अंतर नहीं पड़ पाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिये निम्न उपाय अपनाना आवश्यक है–घरेलू बचत में वृद्धि करना, विदेशी सहायता की निर्भरता कम करना, मुद्रा नीति एवं बैंकिंग नीति का सहयोग लेना, अनावश्यक व्यय को रोकना, मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाना, चोर बाजारी समाप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना, परिवार नियोजन को अपनाना आदि उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

संक्षेप में इन विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था मूलतः पिछड़ी तथा कृषि प्रधान होती है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मूल रूप से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। इसकी कुछ विशेषतायें ऐसी भी हैं, जिनसे इसके विकासशील स्वरूप की झलक दिखाई देती है। भारतीय आर्थिक ढाँचे की अनेक विशेषतायें हैं। इनमें से तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं –

1. अर्थव्यवस्था का द्वैतात्मक स्वरूप

भारतीय अर्थव्यवस्था के दो भाग या क्षेत्र हैं जो एक दूसरे से काफी भिन्न है। एक ओर तो अर्थव्यवस्था का ग्रामीण तथा परम्परागत क्षेत्र है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीण

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

क्षेत्र आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के प्रभाव से अछूता रहा है। आर्थिक जीवन में सामाजिक रीति–रिवाजों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है।

इसके विपरीत भारतीय अर्थव्यवस्था का शहरी अथवा औद्योगिक क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। यहाँ आर्थिक क्रियाओं का संचालन काफी बड़ी सीमा तक व्यवस्थित आधार पर होता है, इस क्षेत्र में लेन–देन (विनिमय) मुद्रा द्वारा होता है। बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध रहतीं हैं। जीवन स्तर ऊँचा रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का यह विकसित क्षेत्र है।

2. मिश्रित अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन दो क्षेत्रों के अन्तर्गत होता है– (अ) सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) और (2) निजी क्षेत्र (Private Sector) सार्वजनिक क्षेत्र का आशय, उस क्षेत्र से है जहाँ संसाधनों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इस क्षेत्र में मूलतः सार्वजनिक हित या कल्याण को ध्यान में रखकर आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है।

इसके विपरीत निजी क्षेत्र में संसाधन लोगों के निजी स्वामित्व में होते हैं। इस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुख्य रूप से निजी लाभ के लिये किया जाता है लेकिन भारत में निजी क्षेत्र स्वतंत्र नहीं है। देश की सुरक्षा एवं देश के समुचित आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये निजी क्षेत्र पर सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाये जाते हैं।

3. योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। आजादी मिलने के बाद देश के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये 1951 से आर्थिक आयोजन की नीति को अपनाया गया है। पाँच–पाँच साल की योजनायें बनाकर विकास के लिये व्यवस्थित प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय आर्थिक आयोजन एक लोकतांत्रिक आयोजन है न कि अधिकेन्द्रित अथवा समाजवादी आयोजन। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक भाग में ही मूल रूप से योजना लागू होती है। शेष भाग का संचालन एक सीमा तक स्वतंत्र रूप में बाजार तंत्र के सहारे होता है।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, उनकी प्राप्ति के लिये अनिवार्यतः अथवा आदेशों की व्यवस्था नहीं की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिये पर्याप्त वित्तीय साधनों एवं उपयुक्त नीतियों का प्रबंध किया जाता है, ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जा सके। उधर निजी क्षेत्र को वांछित दिशा में मोड़ने के लिये तरह–तरह की सुविधाओं, प्रोत्साहन, नियंत्रण, बाजार विनिमयन आदि का समुचित प्रबंध किया जाता है। लोकतंत्रीय आयोजन की यही विशेषता होती है।

इसके विपरीत अधिकेन्द्रित आयोजन के अन्तर्गत सारी अर्थव्यवस्था पर योजना को लागू किया जाता है और महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों के संबंध में लोगों को कोई छूट नहीं होती। यहाँ अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं का केन्द्रीय योजना के अनुसार संचालन करना होता है, जिसके लिये केन्द्रीय आयोजन प्राधिकारी की ओर से आवश्यक आदेश जारी किये जाते हैं।

भारत एक लोकतंत्रीय देश है। इसलिये यहाँ लोकतंत्रीय आयोजन को अपनाया गया है, जिससे लोकतंत्र और आयोजन के लाभ एक साथ प्राप्त किये जा सकें। आज सारे विश्व की आँखें भारत के इस अनोखे एवं महत्त्वपूर्ण प्रयोग की ओर लगी हुई हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विकसित अर्थव्यवस्था का पता लगाना।
2. योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना।
3. वैश्वीकरण की सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन करना।
4. वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों का अध्ययन करना।
5. वैश्वीकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का पता लगाना।

वैश्वीकरण से आशय

वैश्वीकरण शब्द आज अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर गुंजायमान हो रहा है। वैश्वीकरण विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने की व्यापक प्रक्रिया है। जिसमें सम्पूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, जिसमें विश्व

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

बाजारों के मध्य पारंपरिक निर्भरता पैदा होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबन्धित न रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ ने जिसके अहस्तक्षेप की नीति को यह कर परिभाषित किया था कि ''इसमें देशी व्यापार यह कहकर तथा विदेशी व्यापार में कोई अन्तर नहीं किया जाता है।

वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार के प्रयास

वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने आठवें दशक के शुरू में ही प्रयास करने आरंभ कर दिये थे। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत विदेशी पूँजी को बहुत सी रियायतें दी गई। बहुत से ऐसे क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश की अनुमति दी गई जिनमें उन्हें पहले कार्य करने की आज्ञा नहीं थी। विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम को तीव्रता से लागू नहीं किया गया, निर्यातों को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया गया परन्तु वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी भारत सरकार द्वारा जुलाई 1991 मे लागू की गई। आर्थिक नीति के फलस्वरूप आई जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव के कारण अपनाई गई थी। यही कारण है कि वर्तमान आर्थिक नियोजन में वैश्वीकरण को महत्त्व प्रदान कर अपनाया गया है।

भारत सरकार द्वारा 1991 व बाद के वर्षों में पूँजी बाजार एवं वैश्वीकरण करने के उद्देश्य से नीतिगत मामलों में कई फैसले लिए गए। वैश्वीकरण की तरफ उठाए गए प्रमुख कदम निम्न हैं –

1. **पूँजी बाजार में प्रवेश की अनुमति** : भारतीय कम्पनियों को ब्यूरो–इक्विटी शेयरों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार में प्रवेश की अनुमति मिल गई।
2. **उदार मानदण्ड** : भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ही कम्पनियों को पूँजी अंशदान स्वीकार करने तथा अनिवासी भारतीयों या समुद्रीपारीय (निगमित) निकायों को शेयर या डिबेंचर जारी करने की अनुमति देने हेतु अनिवासी भारतीयों के लिए मानदण्डों को उदार बनाया गया।
3. **विदेशी दलालों की सहायता की अनुमति** :विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीयन के पश्चात् भारतीय पूँजी बाजार में निवेश करने की अनुमति दी गई। उनके लिए सामान्य आवेदन–पत्रों को आसान बनाया गया एवं विदेशी दलालों को उनकी सहायता करने की अनुमति दी गई।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

4. **सरलीकरण** : घरेलू तथा विदेशी संस्थागत निवेशकर्ताओं के लिए प्रतिभूतियाँ प्रदान करने के लिये अन्तरण की प्रक्रियाओं को 'त्रम्बों' अन्तर विलख पत्रों और स्टाम्प शुल्क के समेकित भुगतान के माध्यम से काफी आसान बनाया गया।
5. **निवेशकों की समान पहुँच** : वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा राष्ट्रव्यापी स्टॉक व्यापार सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन, समाशोधन तथा निपटान सुविधाओं के स्टॉक एक्सचेंज के रूप में तेजी से प्रतिभूतियों में 'स्क्रिपरहित' तथा 'फ्लोर रहित' व्यापार प्रणाली पर अवलम्बित एक ऐसे राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक परिदृश्य की ओर अग्रसर होगा, जो कारगर और पारदर्शी होगा तथा इसमें निवेशकों की समान एवं राष्ट्रव्यापी पहुँच होगी।
6. **विदेशियों को बैंक व परिरक्षा खाते खोलने की अनुमति** :विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेन–देन में विदेशी दलालों की भूमिका को बढ़ाकर सुविधाजनक बनाया जा रहा है। विदेशी दलाल विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के आदेश के प्रेषण द्वारा परिचालन कर सकेंगें। इन विदेशी दलालों को इन प्रयोजनार्थ बैंक और परिरक्षा खाते खोलने की आज्ञा दी गयी।
7. **केन्द्रीय जमा घर की स्थापना** : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पूँजी निवेशकों की माँग के अनुरूप भारत में केन्द्रीय जमा घर की स्थापना किये जाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए अलग से कानून बनाया जायेगा। प्रतिभूति एवं नियमन बोर्ड अधिनियम एवं प्रतिभूति नियंत्रण विनिमय में तदनुसार संशोधन किए जायेंगें।

वैश्वीकरण का प्रभाव

1. वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतिद्वन्द्विता बढ़ती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है।
2. उपभोक्ताओं को चयन की बेहतर स्वतंत्रता प्राप्त होती है क्योंकि एक ही वस्तु का उत्पादन अनेक उत्पादकों द्वारा किया जाता है।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

3. प्रतियोगिता के कारण देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है। जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक उन्नति की गति तीव्र होती है।
4. वैश्वीकरण में राष्ट्र को विदेशी पूँजी का लाभ प्राप्त होता है जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक उन्नति की गति होती है।
5. वैश्वीकरण में राष्ट्रीय उद्योगों की वैदेशिक सम्बद्धता में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ोत्तरी होती है।

वैश्वीकरण को सफल बनाने हेतु सुझाव

वैश्वीकरण मे विद्यमान दुर्बलताओं के बावजूद भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वैश्वीकरण एक स्वाभाविक एवं अवश्यम्भावी प्रक्रिया है। अतः जरूरत इसे खत्म करने की नहीं वरन् इसमे सुधार लाने की है। इस प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं –

1. वैश्वीकरण की प्रक्रियाकरण के नाम पर किये जा रहे स्थानीय तथा संकीर्ण लक्ष्यों को विश्वस्तरीय आन्दोलनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाये।
2. मुक्त व्यापार नीतियों को दबावों से मुक्त करके अपनाया तथा क्रियान्वित किया जाये।
3. विश्व सहयोग में वृद्धि हेतु कार्यरत कई क्षेत्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अधिक सक्रियता से एवं कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिए।
4. वैश्वीकरण के सम्भावित खतरों को विश्वस्तर पर सामूहिक प्रयत्न किया जाये।
5. विश्व स्तर के प्रशासन के लिए नवीन संरचनाओं की स्थापना की गयी।
6. वैश्वीकरण के पुनर्नियमन के द्वारा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विकास किया जाये।
7. वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्यों एवं व्यक्तियों पर होने वाले हानिकारक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय एवं सांस्कृतिक प्रभावो को खत्म किया जाये।

इसी तरह वैश्वीकरण को अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि की एक उत्तम प्रक्रिया के रूप में अपनाया जा सकता है।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

निष्कर्ष

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण के ऐसे स्वरूप को अपनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा विकास, रोजगार और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके एवं ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे श्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को रोका जा सके। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक आधार को मजबूत बनाया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर इसकी वृद्धि दरों को उन्नत किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था– एस.के. मिश्र, वी.के. पुरी।
2. आर्थिक समीक्षा– 2010–11
3. भारतीय अर्थव्यवस्था– 2011–12
4. दैनिक भास्कर समाचार पत्र।
5. नई दुनियाँ समाचार पत्र।
6. प्रतियोगिता दर्पण।